ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बांध 30-5-1974 को पूरा हो गया था ।

(घ) राजस्थान मे 1.2 मिलियन हैक्टेयर, पंजाब मे और हरियाणा में 0.4 मिलियन हैक्टेयर ।

(ङ) प्रथम चरण मे पोंग बाध बिजली पर की प्रतिष्ठापित क्षमता 240,000 किलोवाट होगी ।

Shortage of X-ray films in Maharashtra

1478. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is acute shortage of X-ray films in the country, specially in Maharashtra;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI B P. MAURYA): (a) and (b) Government have not received any reports regarding the acute shortage of X-ray films in the country, specially in Maharashtra.

(c) The present production of medical X-ray films at Hindustan Photo Films Manufacturing Co Ltd., Ootacamund, is adequate to meet the country's demand. The Company has built up adequate stocks both at the plant level and at the distributors' level. It has also set up Quick Service Centres at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras to meet any temporary shortages at the distributors' level. Through these Centres, the company can meet the immediate requirements of any Radiologist within a few days increase the stock is not available with the distributors.

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिये ऋण और अग्रिम धनराशियां

1479. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिये केन्द्रीय अनुदान के रूप में 10 करोड रुपये की राशि की राजसहायता मंजूर करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या पिछड़े तथा विकसित राज्यों को राजसहायता मजूर करने के मामले में एक रूपता नही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असन्तुलन को दूर करने और पिछड़े राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को अधिक सहायता मंजूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) राजसहायता समान रूप से न दी जाकर कार्य करने के आधार पर मजूर की जाती है ।

(ग) इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही मुख्य रूप से राज्य सरकारों को करनी होती है क्योंकि इस प्रकार की राजसहायता कार्य के आधार पर दी जाती है । फिर भी, भारत सरकार विशेष रूप से उन राज्य सरकारों से जिनमें योजना का प्रभाव अधिक नही पड़ा है, सम्पर्क बनाये हुये है ताकि जिससे उनके कार्य में सुधार करने के लिये उचित मार्ग दर्शन दिया जा सके । उद्योग मंत्री ने इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस बारे में पहले ही लिख दिया है ।